विचार बिन्दु

हमारे कष्ट पापों का प्रायश्चित है। –हज़रत मोहम्मद

डॉ. मनमोहन सिंह की विरासत

डॉ. मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर सिंह की पहचान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं थी, अपितु वे 1991 के वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के जनक भी रहे। उन्होंने जून 1991 में जब वित्त मंत्री के पद का कार्यभार संभाला तो भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत डांवाडोल थी और विदेशी मुद्रा का भंडार केवल दो सप्ताह के भुगतान तक का शेष बचा था । ऐसे संकट के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी वित्तीय कुशलता, आर्थिक मामलों की विशेषज्ञता का परिचय देते हुए भारत को न केवल एक बहुत ही कठिन संकट से उबारा अपितु भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का कार्य किया। उन्हीं के कार्यकाल में कोटा, परमिट, लाइसेंस राज से देश की लगभग विदाई हुई और निजी क्षेत्र को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कर विज्ञान, तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यंत तेजी से प्रगति की। शीघ्र ही, भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में गिना जाने लगा। डॉक्टर सिंह की पहचान केवल एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में ही नहीं थी एवं न इस रूप में थी कि वे रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर रहे थे एवं वित्तीय मामलों के भारत सरकार में सचिव रहे थे । उनके सबसे बड़े गुण उनकी सादगी, अहमरहित व्यवहार, विनम्रता थे जो आजकल किसी राजनेता में विरले ही दिखाई देते हैं।

हमने गत तीन महीने में दो प्रमुख भारतीय हस्तियों को खोया है जिनमें एक रतन टाटा थे और दूसरे अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं।

डॉ. मनमोहन सिंह इसका अच्छा उदाहरण हैं कि कैसे स्वतंत्रता के समय 1947 में शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान वाले पंजाब से भारत आने वाला बालक अपनी लगन, निष्ठा और प्रतिभा के बल पर, देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा और कैसे अपनी प्रतिभा का लोहा न केवल अपने देशवासियों को बल्कि पूरे विश्व को मनवाया।

वित्त मंत्री के रूप में उनके भारतीय संसद एवं वैश्विक मंचों पर दिए गए भाषण अत्यंत विद्वतापूर्ण किंतु बड़े सरल होते थे । हालांकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, किंतु फिर भी उर्दू मिश्रित हिंदी में वह अपनी बात बड़ी सहजता और सरलता से कर लेते थे। उनमें अर्थव्यवस्था की जटिल बातों को बड़ी सरलता से देशवासियों को समझाने की अद्भुत सामर्थ्य थी। आज के जमाने में, यह सरलता और सहजता बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके जीते जाते उदाहरण थे ।

उन्होंने अपनी भाषा की गरिमा को सदैव बनाए रखा।

उनके प्रधानमंत्री रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव के निर्णय लिए गए। उनके समय में देश के आम जन के हित के अनेक कानून बनाए गए जैसे रोजगार के अधिकार का कानून (नरेगा), सूचना के अधिकार का कानून, शिक्षा के अधिकार का कानून, खाद्य सुरक्षा का कानून आदि। उनके प्रधानमंत्रित्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर समझौता किया, जिसके कारण उनकी सरकार तक गिरने की नौबत आ गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तर्क शक्ति से, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए, इसकी परवाह नहीं की एवं इस न्यूक्लियर डील को संसद से अनुमोदित कराया। वे कम्युनिस्ट पार्टी की धमकियों के आगे नहीं झुके। देश के लिए न्यूक्लियर डील बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

अहम उनको छू भी नहीं गया था । उन्होंने कभी भी अपने पद का लाभ नहीं उठाया। उनके दूसरे कार्यकाल में 2009 से 2014 के बीच कोयला विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे किंतु वह व्यक्तिगत रूप से सदैव बेदाग ही रहे । जिस प्रकार राहुल गांधी ने कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता में फाड़ दिया और उसके बाद सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा। वह उनके लिए बड़ी अपमानजक स्थिति थी । यदि और कोई साधारण नेता होता तो उसके बाद उसने तत्काल इस्तीफा दे दिया होता। डॉ मनमोहन सिंह ने इसके बावजूद यदि अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो इसका कारण, उनकी पद लोलुपता नहीं थी, अपितु अपनी पार्टी और राष्ट्र का हित था । उन्होंने व्यक्तिगत अपमान का घूंट पीने के बावजूद हल्की भाषा का उपयोग नहीं किया । आज के उन राजनेताओं को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए, जो प्रतिदिन संवाद का स्तर गिराने का काम कर रहे हैं। डॉ. मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी विरासत ही यह है कि उन्होंने राजनीति में भाषा की गरिमा को बनाए रखा और विरोधियों के प्रति भी कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया।

भाजपा के नेताओं ने विशेष कर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को 'मौन' मोहन का नाम देते हुए उनकी कार्य शैली का कई बार मजाक बनाया किंतु उन्होंने अपनी भाषा को कभी हल्का नहीं किया एवं अपने ही अंदाज में शालीन भाषा में उसका उत्तर दिया । जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि इसके कारण कुछ समय तक लोगों को परेशानी हो सकती है किंतु दीर्घकालीन दृष्टि से इसका बहुत लाभ है, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी सरलता से यह कहा कि ''दीर्घ काल में तो सबकी मृत्यु ही होती है''।

उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियां का गुणगान नहीं किया। शायद इसी उदारता और विनम्रता की कीमत उन्हें व्यक्तिगत रूप से चुकानी पड़ी। गांधी परिवार ने हालांकि उनको प्रधानमंत्री बनाया अवश्य, किंतु उनके साथ व्यवहार कई बार अपेक्षित गरिमा वाला नहीं किया। उनकी स्थिति को दर्शाते हुए एक पुस्तक संजय बारु ने ''दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर'' के नाम से लिखी। बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें अनुपम खेर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका निभाई।

हालांकि भाजपा के नेताओं ने विशेष कर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को 'मौन' मोहन का नाम देते हुए उनकी कार्य शैली का कई बार मजाक बनाया किंतु उन्होंने अपनी भाषा को कभी हल्का नहीं किया एवं अपने ही अंदाज में शालीन भाषा में उसका उत्तर दिया । जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि इसके कारण कुछ समय तक लोगों को परेशानी हो सकती है किंतु दीर्घकालीन दृष्टि से इसका बहुत लाभ है, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी सरलता से यह कहा कि ''दीर्घ काल में तो सबकी मृत्यु ही होती है''। इसका अर्थ समझने वाले समझ गए और उन्होंने बहुत बड़ी बात बड़ी सरलता से समझा दी। कालांतर में, उनकी कही गई बात अक्षरशः सही साबित हुई।

अर्थशास्त्र पर उनकी पकड़ के सभी कायल थे।

उनके निधन के बाद विभिन्न दलों के नेता उनके गुणों का बखान करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। काश, उनकी विद्वता और गुणों की पहचान करके उनका सम्मान उनके जीवित रहते हुए भाजपा के नेताओं द्वारा किया जाता। यह उन्होंने कई बार कहा कि उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत है। शायद वह सही भी थे, क्योंकि आजकल जिस प्रकार की भाषा में आरोप प्रत्यारोप किये जा रहे हैं और लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार हो रही है, उसको देखते हुए संभवतया उनकी खामोशी विशिष्ट थी और बहुत शक्तिशाली भी साबित हुई । वह बहुत कड़े निर्णय लेने की क्षमता रखते थे।

2014 से 2024 के बीच भाजपा के अनेक नेता एवं प्रधानमंत्री मोदी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कड़ी आलोचना की एवं डॉक्टर सिंह को एक अत्यंत कमजोर प्रधानमंत्री बताया। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के बड़प्पन और शालीनता को ही दर्शाता है कि उनकी इतनी कड़ी आलोचना के बाद भी उन्होंने कभी भाषा की मर्यादा को नहीं छोड़ा।

डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा का एक ही चुनाव लड़ा जिसमें वह असफल रहे। वे छह बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उनकी कोई 'मासअपील' नहीं थी किंतु उनकी सादगी उनकी पहचान थी।

अब, जब वे दुनिया में नहीं हैं तो उनकी विरासत पर बात होनी चाहिए। उन्हें दिखावे से कतई मोह नहीं था, न उनके लिए कुर्सी पर बने रहना बहुत महत्वपूर्ण था ।

उनके दो कार्यकाल में से पहला कार्यकाल जो 2004 से 2009 तक का था , को श्रेष्ठ कहा जा सकता है, जबकि वह एक अल्पमत सरकार के मुखिया थे । 2009 से 2014 के दूसरे कार्यकाल में जबकि कांग्रेस को कुछ सीटें अधिक मिलीं, इस कार्यकाल में 'पॉलिसी पैरालिसिस' शब्द काफी प्रचलित रहा और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उनके मंत्रियों पर कई आरोप लगे जिसने अन्ना आंदोलन को जन्म दिया। इसका खामियाजा कांग्रेस को 2014 के चुनाव में उठाना पड़ा । इस चुनाव में कांग्रेस को अब तक की न्यूनतम सीटें 52 प्राप्त हुईं। अच्छा होता, यदि इसके बाद डॉक्टर सिंह सक्रिय राजनीति से अलग हो जाते, किंतु शायद सोनिया गांधी का दबाव ही था कि वे इसके बाद भी 6-7 सालों तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे।

कुल मिलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत यही है कि कैसे अत्यंत ही साधारण परिस्थितियों से निकलकर कोई व्यक्ति केवल अपनी योग्यता और गुणों के बल पर सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। एक ओर जहां अपनी ताकत दिखाने का प्रचलन है, वहीं वे अपने पद का प्रयोग किए बिना बहुत बड़े निर्णय ले पाए जो दूरगामी सिद्ध हुए। आर्थिक दृष्टि से तो उनका कोई सानी नहीं था । यू पी ए के दस सालों के कार्यकाल में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी जिसे बाद में एनडीए की सरकार ने संशोधित करके 6.8 प्रतिशत कर दिया। आर्थिक दृष्टि से सही था या नहीं, कहना कठिन है ।

आज जब जहां गला काट प्रतियोगिता हर क्षेत्र में चल रही है, वहां युवाओं के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक वैकल्पिक रोल मॉडल के रूप में सामने आते हैं । उनकी छवि एक उदार, विनम्र, मानवतावादी और देशभक्त अर्थशास्त्री की रही है। अब यह हम सब पर है कि हम उनकी विरासत को कितना आगे बढ़ा पाते हैं और सार्वजनिक जीवन में सादगी और विनम्रता को प्रतिष्ठापित कर पाते हैं।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

प्रशासनिक परिपक्वता का परिचायक है जिलों की समाप्ति का निर्णय

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

राजस्थान सरकार की इस कारण से सराहना करनी पडेगी कि राजनीतिक दृष्टि से निर्णय लेना मुश्किल व जोखिम भरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार के समय के जिले बनाने के निर्णय का परीक्षण कर 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अब प्रदेश में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ठाामीण और सांचौर जिला और बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यही निर्णय नई सरकार बनते ही लिया जाता तो उसके मायने कुछ अलग होते और उस पर राजनीतिक द्वेषता का ठप्पा लगता वह अलग होता। आज भले ही विपक्ष द्वारा इस निर्णय पर प्रश्न उठाये जा रहे हो पर सही मायने में देखा जाए तो यह पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णय है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार के नए जिले बनाने के निर्णय का परीक्षण करने के लिए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डा.ललित पंवार की अध्यक्षता में समिति गठित कर परीक्षण करवाया और फिर राजनीतिक स्तर पर मंत्रीमण्डलीय समिति बनाकर सभी पक्षों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्राप्त की और उसके भी बाद निर्णय पर मंत्रीमण्डल की बैठक में मोहर लगाई गई। इसलिए एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि यह निर्णय किसी भी मायने में राजनीतिक लाभ के लिए ना होकर पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता के लिए लिया गया निर्णय है। ना ही इसे जल्दबाजी में निर्णय कहा जा सकता है। हांलाकि पूर्व सरकार ने नए जिले बनाने के लिए भले ही प्रशासनिक कमेटी बनाकर रिपोर्ट प्राप्त कर नए जिले बनाने का निर्णय किया पर यह सब अच्छी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि चुनाव नजदीक होने के कारण पूर्व सरकार द्वारा नए जिले बनाने के निर्णय को आमलोगों ने पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय के रुप में ही देखा गया।

भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार द्वारा गठित नए जिलों के गठन का प्रशासनिक दृष्टि से परीक्षण करवाया और इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआत में इन जिलों और संभागों को समाप्त करने के निर्णय का विरोध हो पर यह विरोध इसलिए अधिक असर नहीं दिखा पाएगा कि आमनागरिक यह अच्छी तरह से समझता है कि अधिक और छोटे जिले बनने से सरकारी खर्चें अधिक बढ़ने के अलावा कोई खास प्राप्त होने वाला नहीं है। नए जिलों को लेकर यदि सामान्य नागरिक के रुप में हम स्वयं परीक्षण करे तो साफ हो जाता है कि शुरुआती दौर में ही एक जिले के लिए कम से कम एक हजार करोड़ की व्यवस्था करनी होगी। जिला कलक्टर और जिला पुलिस एसपी के दफ्तर तो तत्काल शुरु करने के साथ ही अन्य विभागों के भी दफ्तर जिला स्तर पर खोलने से ही वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है। अब इसे यों देखा जाए कि इस सबके लिए कितना बड़ा प्रशासनिक अमला तैयार करना होगा, कितनी अधिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होगी। सरकारी ऑफिस, सरकारी बंगले और ना जाने कितने ही कार्यों के लिए स्थान और आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं और अन्य सेवाएं अलग होगी। हमारे सामने पुराने उदाहरण है जब राजसमंद, प्रतापगढ, दौसा जिले बनाए गए और करौली व प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। अब सबके सामने है कि इन जिलों को सही मायने में जिलो का आकार लेने में कितना समय लगा। आज भी कई स्थानों पर फिजिबल नहीं होने के कारण जिला सहकारी बैंक नहीं खुल पाएं है तो कई अन्य सरकारी दफ्तर शुरु नहीं हो पाये हैं।

दरअसर जनहितकारी सरकार की पहचान लोकहित में दूरगामी परिणामों को देखते हुए निर्णय लेना होता है। हांलाकि लोकतंत्र में बहुत से निर्णय राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण न चाहते हुए भी लेने होते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ऐन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं। प्रशासनिक दक्षता और लोकहितकारी सरकार की पहचान जनहित में कड़बे निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करना होता है। सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता का भी इसी से पता चलता है। खासतौर से राजनीतिक लाभ हानि से लिए गए निर्णय से अधिक भला नहीं हो पाता है। सरकार की प्रशासनिक और लोकहितकारी होने का इसी से पता चलता है कि वह जनहित में जोखिमभरे निर्णय लेने में भी कोई संकोच ना करें। लोकतंत्र में जनता और जनता का हित बड़ी बात होनी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा निर्णयों का असर दूर तक जाता है। कड़बे निर्णय यदि लोकहित में होते हैं तो जनता समझने में देरी नहीं लगाती। इसलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकार बनने के पहले साल में ही बड़े निर्णय कर सबको चौंका दिया है। राजनीतिक लाभ हानि से परे हटकर मुख्यमंत्री ने 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का निर्णय व्यापक जनहित में ही देखा जाना चाहिए।

एक और यह कहा जाता है कि सरकार राजस्व का अधिकांश खर्चा अपने प्रशासनिक दायित्वों वेतन-सुविधाओं में ही खर्च कर देती है वहीं नए जिले और संभाग बनने से प्रशासनिक खर्च बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि नए जिले या संभाग बनाने के स्थान पर सरकारों को प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजनीतिक जोखिम लेते हुए प्रशासनिक दृष्टि से सराहनीय निर्णय किया है। इससे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से परिपक्वता का परिचय दिया है। हो सकता है कि निर्णय को लेकर विरोध देखने को मिले पर विरोध के खिलाफ भी सरकार को सख्ती दिखानी होगी इससे आमजन में सरकार और सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को सराहा ही जाएगा।

–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

इस यातायात का बोझ कौन उठाएगा?

रामगोपाल जाट

भारत विकास कर रहा है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो देखा, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे थे कि आज अमेरिका, चीन और भारत के बाद रूस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथी दो साल से कह रहे हैं कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होगा। यह बात सही भी जान पड़ती है कि जब विश्व के सभी देश भारत के साथ मिलकर चलने का बेताब दिखाई दे रहे हैं, आज भारत विश्व में जनसंख्या के अनुसार पहले पायदान पर पहुंच चुका है, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, दुनिया की हर छोटी-बड़ी कंपनी भारत में आकर कारोबार करना चाहती है, तब ठीक ही जान पड़ता है कि भारत से आगे अमेरिका और चीन ही हैं। कोरोना के बाद अचानक से जिस तरह वैश्विक कंपनियों ने चीन से मुंह मोड़ा, उसका लाभ भारत को मिला ही है। एप्पल जैसा ब्रांड अपना उत्पादन 25 तक भारत में करना चाहता है। 5-6 साल पहले तक भारत एक रुपये का भी मोबाइल निर्यात नहीं करता था, लेकिन आज दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। आने वाले तीन साल का अनुमान लगाया गया है कि पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। पूरे विश्व में भारत बड़े पैमाने पर चोपहिया और दुपहिया वाहन निर्यात कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में भारत जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे जान पड़ता है कि यात्री वाहनों के स्तर पर आने वाले 8-10 वर्षों में हम डीजल वाहनों को बंद ही कर देंगे। सड़कों पर देखेंगे तो हर तीसरा या चौथा वाहन इलेक्ट्रिक दिखाई दे रहा है।

जिस गति से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसी गति से सड़कों पर जगह कम होती जा रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास की भांति देश में जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे दूसरी श्रेणी के शहरों में यातायात दबाव ने राहगीरों के प्राण हलक में लाने का काम किया है। अकेले जयपुर की बात की जाए तो पिछले 10 वर्षों में वाहनों की संख्या दोगुनी से अधिक बढ़ी है, लेकिन सड़कें वही हैं। कुछ सड़कों की चोडाई को छोड़ दें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। जयपुर की हर सड़क यातायात के दबाव से कराह रही है। शहर के वीआईपी मार्गों को छोड़ दिया जाए तो यातायात पुलिसकर्मी भी नहीं मिलते। सुबह-शाम का जाम लोगों की कमर तोड़ रहा है। लाल बत्तियों पर खड़े वाहनों और जाम में फंसे राहगीरों का अधिकांश ईंधन तो सड़क पर खड़े-खड़े ही जल रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में बताया गया कि जयपुर के वाहनों की औसत रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसमें भी सुबह-शाम की बात करें तो घटकर 12-13 किलोमीटर रह जाती है। सीएम, मंत्री या अधिकारियों के लिए सड़कों पर पुलिसकर्मी तैयार बैठे हैं, लेकिन आजकल के हालात ये हो गए हैं कि एम्बुलेंस तक को लोग रास्ता नहीं दे पाते हैं।

आगे वाहन, बगल में गाड़ी, दायें मोटरसाइकिल, अब इसके बाद यदि एम्बुलेंस पीछे से सायरन बजाती रहे तो भी वाहन चालक करेगा क्या? जिस गति से वाहनों की संख्या सड़कों पर बढ़ रही है, उसी गति से यातायात जाम की दुगर्ति बनती जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि जयपुर शहर की जनसंख्या के अनुसार कम से कम 1000 लो फ्लोर बसों की आवश्यकता है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो आज करीब 150 बसें बची हैं, जिनमें से भी 50 बसें अगले महीने खटारा हो जाएंगी। उसके बाद केवल 100 बसें बचेंगी, यानी आवश्यकता के मुकाबले केवल 10 फीसदी। आप अंदाजा लगा लीजिए की जाम आखिर होता क्यों है? जब सार्वजनिक वाहन होंगे ही नहीं, तो फिर लोग अपने वाहनों से यात्रा करने को मजबूर होंगे ही। जिसके पास कुछ नहीं है, वो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, जिसके पास दुपहिया वाहन है, वो छोटी कार लाना चाहता है और जिसके पास छोटी कार है, वो बड़ी कार की सवारी करना चाहता है। यह होड़ इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि सरकारों ने सार्वजनिक यातायात को कमजोर कर दिया है।

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, यानी जेसीटीएसएल की स्थापना तत्कालीन भाजपा वाली वसुंधरा राजे सरकार ने 400 बसों के साथ की थी। इसमें 50 फीसदी केंद्र सरकार का, 20 प्रतिशत राज्य सरकार की सहायता और 30 प्रतिशत हिस्सा निकाय का होगा। तब यह तर्क दिया गया था कि जयपुर के यातायात को सुगम बनाने के लिए सरकारी सहायता से बसों का बड़ा बेडा तैयार किया जाएगा, जिससे शहर में चोपहिया वाहन नहीं बढ़ें, लेकिन उसके बाद आई कांठोस की अशोक गहलोत सरकार ने इसपर ध्यान ही नहीं किया। फिर 2013 में वसुंधरा की दूसरी सरकार आई तो इस योजना पर थोड़ा काम किया गया, लेकिन 2018 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई और जेसीटीएसएल का पतन शुरू हो गया। आज की हालत क्या है, यह किसी से छुपा नहीं है।

जब सरकार सार्वजनिक यातायात बढ़ायेगी नहीं, जनसंख्या दबाव बढ़ेगा तो वाहनों की संख्या स्वतः ही बढ़ेगी और उसके उपरांत क्या होगा, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः सरकार को चाहिए कि अविलंब जेसीटीएसएल को मजबूत किया जाए, बसों की संख्या तुरंत प्रभाव से बढ़ाई जाए और लोगों को सार्वजनिक यातायात के लिए जागरूक किया जाए। किंतु आज शहरों के यातायात दबाव को नियंत्रित करने की सरकारी योजना की कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है। 2018 में यातायात मंत्री बने प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़े दावे किये, लेकिन पांच साल में एक बस नहीं आई। उसके बाद वर्तमान सरकार को एक साल हो गया, लेकिन यही पता नहीं कि यातायात मंत्री कौन हैं। ऐसे ही सरकार में अधिकारियों की स्थिति है, जिनको आदेश निकालने होते हैं, लेकिन उनके निकाले आदेश कभी पूरे ही नहीं होते। नेता, अधिकारी सरकार और पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यातायात को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता।

–रामगोपाल जाट,,
वरिष्ठ पत्रकार

जितेंद्र सिंह के निधन पर परिजनों ने पार्थिव देह की दान

बीकानेर कैलाशपुरी निवासी 82 वर्षीय सेवा निवृत जज जितेंद्र सिंह यादव के निधन होने पर परिजनों ने देह दान की।

बीकानेर । कैलाशपुरी निवासी 82 वर्षीय सेवा निवृत जज जितेंद्र सिंह यादव का सोमवार को निधन होने पर परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार यादव के पार्थिव देह को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के एनाटॉमी विभाग को दान किया। परिजनों ने बताया कि यादव दूरदर्शी सोच रखते थे वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी देह दान का संकल्प लिया ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रायोगिक अध्ययन एवं शोध कार्य में कोई परेशानी नहीं आए।

इस दौरान सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी ने पुष्पांजलि अर्पित कर यादव की पार्थिव देह को नमन किया, और परिजनों को दुःख की घड़ी में ढांढस बंधाते हुए कहा कि इनके इस निर्णय से अन्य व्यक्ति जागरूक होकर देह दान को लेकर जागरूक होंगे परिणाम स्वरूप सर्व समाज को कुशल चिकित्सक उपलब्ध हो पाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी लगातार सर्व समाज मे देह दान के प्रति जागरूकता का संदेश देने का अभियान चला रहे है।

देग में पकता है शुद्ध शाकाहारी भोजन

अजमेर, । सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में दुनिया के सबसे बड़ी देग है। यह बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर ने दरगाह में भेंट की थी। बड़ी देग में 120 मन यानी 4800 किलो चावल एक साथ पकाया जाता है, ऐसी ही एक देग और भी है जो छोटी देग के नाम से जानी जाती हैं। इसमें एक बार में 60 मन चावल पकाए जाते है, छोटी देग को जहांगीर ने बनवाया था। देग में पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी बकाई जाती है। ख्वाजा साहब के उर्स में 15 दिनों के लिए देग का ठेका भी छूटता है। 813वें ख्वाजा साहब के सालाना उर्स के मौके पर इस बार 2 करोड़ 68 लाख रुपए का ठेका छूटा है। खादिम कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद दरवाजे के समीप एक ओर बड़ी और दूसरी ओर छोटी देग है। बड़ी देग दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन बताया जाता है, ये देग मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी। बताया जाता है कि मुगल बादशाह ने औलाद होने की मन्नत पूरी होने पर यह बड़ी देग भेंट की, इतिहास में दर्ज है कि मुगल बादशाह अकबर की ख्वाजा गरीब नवाज में गहरी आस्था थी। औलाद की मन्नत पूरी होने के बाद वो आगरा से अजमेर तक पैदल चल कर आया था, उस वक्त अकबर ने दरगाह में बुलंद दरवाजे के पास दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बड़ी देग बनवाई थी।

देग में पकता है शुद्ध शाकाहारी भोजन : खादिम सकी ने बताया कि छोटी और बड़ी देग में पुर्णतः शुद्ध शाकाहारी भोजन पकाया जाता है। आस्था के अनुयप अकीदत में मीठे चावल ही पकवाते हैं। सकी ने बताया कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर सभी धर्म और जाति के लोग आते है, यही वजह है कि छोटी और बड़ी देग में कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं पकाया गया और न ही लहसुन प्याज का कभी इसमें उपयोग नहीं किया गया, केवल मीठे चावल ही पकाए जाते हैं जो रात में पकते हैं और सुबह जायरीनों में तकसीम किए जाते है। उन्होंने बताया कि अंजुमन कमेटी देग की देख रेख और ठेके का काम देखती है, उर्स के मौके पर हर रोज छोटी देग में तबर्रुक पकाया जाता है।

मन्नत पूरी होने पर पकवाते है देग : दरगाह परिसर में मौजूद बड़ी और छोटी देग जायरीन की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई। ख्वाजा गरीब नवाज से मन्नत पूरी होने पर अपनी आस्था और क्षमता के अनुसार अकीदत देग पकवाते हैं और लंगर तकसीम करते है। जायरीन देगों में पैसा, जेवर, शक्कर, चावल, मेवे अपनी श्रद्धा के अनुसार डालते हैं ताकि लंगर में सहयोग हो सके।

ख्वाजा साहब जौ का दलिया खाते थे: खादिम सकी ने बताया कि अजमेरी बाबा के दर पर भूखा न रहे कोई देगों में पकने वाला मीठा चावल रोज जायरीन को तकसीम कर दिया जाता है। दरगाह के लंगर खाने में दो बड़े कड़ाव और भी हैं, जहां परंपरागत जौ का दलिया ही पकाया जाता है। बताया जाता है कि अजमेर आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने जीवन काल में जौ का दलिया ही खाया करते थे, ऐसे में आज भी परंपरागत तरीके से ही जौ का दलिया बनाया जाता है, और लोगों में तकसीम किया जाता है, ताकि बाबा के दर से कोई भूखा न जाए।

2.68 करोड़ में छूटा ठेका: ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के लिए दरगाह की छोटी व बड़ी देग का ठेका 2 करोड़ 68 लाख रुपए में छूटा है। अंजुमन के सदस्य गफ्फार हुसैन काजमी ने बताया कि उर्स के 15 दिनों के लिए देग के ठेक की बोली 2 करोड़ 6 लाख रुपए में छूटी है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 31 दिसम्बर, 2024

पौष मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 12:04 तक, ध्रुव योग सायं 6:59 तक, किस्तुघ्न करण दिन 3:34 तक, चन्द्रमा बुधवार प्रातः 6:01 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

त्रिपुष्कर योग रात्रि 3:22 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:55 से 11:12 तक, लाभ-अमृत 11:12 से 1:47 तक, शुभ 3:05 से 4:22 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:40

मेष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य से संबंधित यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए आवश्यक कार्य बनने लगेंगे।

सिंह
आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

वृश्चिक
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जा सकते हैं।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।